

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकरण से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]

No. 185]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 14, 2007/भाद्र 23, 1929  
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 14, 2007/BHADRA 23, 1929

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2007

घरेलू लीज्ड सर्किट विनियम, 2007

(2007 का 10)

पा. सं. 404-1/2007-एफएन.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

### अध्याय I

#### प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों को घरेलू लीज्ड सर्किट विनियम, 2007 कहा जाएगा ।  
(2) ये भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- प्रयोग्यता.—ये विनियम प्रत्येक ऐसे प्रत्येक सेवा प्रदाता पर लागू होंगे जो उसके लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अंतर्गत लीज्ड सर्किटों के प्रावधान के लिए सब्सक्राइबरों को प्रत्यक्षतः एक्सेस कर सकता है ।

3. परिमाणाएँ: इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "घरेलू लीजड सर्किट" से अभिप्रेत है किसी सब्सक्राइबर के परिसरों तक कोई लीजड सर्किट जब ऐसे परिसर भारत के भीतर अवस्थित हों;

(घ) "लीजड सर्किट" से अभिप्रेत है प्वाइंट-टु-प्वाइंट नॉन-स्विच्ड भौतिक कनेक्शनों अथवा संप्रेषण बैंडविथ के अलावा सर्किट अथवा पैकेट स्विच्ड (इंटरनेट प्रोटोकॉल) प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तथा जिससे पब्लिक नेटवर्क जुड़ा नहीं है;

(ङ) "लाइसेंस" से अभिप्रेत है प्रदत्त अथवा प्रभाव रखने वाला लाइसेंस, जैसेकि यह भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 तथा भारतीय टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) के अंतर्गत दिया गया है;

(च) "लाइसेंसी" से अभिप्रेत है विनिर्दिष्ट सार्वजनिक दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया गया कोई व्यक्ति;

(छ) "घरेलू लीजड सर्किट की स्थानीय लीड" से अभिप्रेत है सब्सक्राइबर के परिसरों से निकटतम एक्सचेंज के बीच लीजड सर्किट जिसमें शामिल है शार्ट डिस्टेंस चार्जिंग सेंटर, सेवा प्रदाता का प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन और प्वाइंट ऑफ प्रजेंस जिससे सब्सक्राइबर घरेलू लीजड सर्किट प्राप्त करता है;

(ज) "लांग डिस्टेंस चार्जिंग एरिया" से अभिप्रेत है ऐसे अनेक क्षेत्रों, जिनमें देश विभाजित है, मैं से एक क्षेत्र तथा जिसे ट्रंक कॉलों के प्रभारण के प्रयोजन के लिए इस रूप में घोषित किया गया है जो सामान्यतया सेकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्र के साथ सह-स्थानिक है;

## (अ) "प्रमुख सेवा प्रदाता" से,—

(क) किसी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अथवा क्लोज्ड यूजर ग्रुपों में दो अथवा अधिक सेवा प्रदाताओं द्वारा, यथास्थिति, घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीज्ड के मामले में अभिप्रेत है, ऐसा सेवा प्रदाता जिसके पास ऐसे घरेलू लीज्ड सर्किटों को प्रदान करने के लिए सब्सक्राइबर के साथ करार है;

(ख) यदि कोई सब्सक्राइबर अपने क्लोज यूजर ग्रुपों के प्रयोजनों के लिए दो अथवा अधिक सेवा प्रदाताओं से घरेलू लीज्ड सर्किट प्राप्त करता है, तो अभिप्रेत है सभी ऐसे सेवा प्रदाता जो ऐसे क्लोज यूजर ग्रुपों के घरेलू लीज्ड सर्किट प्रदान कर रहे हैं तथा जिनका ऐसे सब्सक्राइबरों के साथ करार है;

(अ) "विनियमों" से घरेलू लीज्ड सर्किट विनियम, 2007 अभिप्रेत है;

(ट) "शार्ट डिस्टेंस चार्जिंग सेंटर" से अभिप्रेत है ऐसे अनेक क्षेत्रों, जिनमें लॉग डिस्टेंस चार्जिंग क्षेत्र विभाजित है, में से एक क्षेत्र तथा जिसे ट्रॅक कॉलों के लिए प्रभारण के प्रयोजन के लिए इस रूप में घोषित किया गया है तथा जिसके भीतर स्थानीय कॉल प्रभार और स्थानीय संख्यांकन स्कीम लागू है तथा ऐसा क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में राजस्व तहसीलों अथवा तालुक के समान (कुछ अपवादों को छोड़कर) है;

(ठ) "सब्सक्राइबर" में शामिल है कोई सब्सक्राइबर अथवा कोई व्यक्ति अथवा विधिक सत्ता, जो घरेलू लीज्ड सर्किट होने के नाते किसी लाइसेंसी से कोई सेवा सब्सक्राइबर अथवा प्राप्त करती है;

(ड) "सेवा प्रदाता" से अभिप्रेत है सेवा प्रदाता के रूप में सरकार तथा इसमें शामिल है कोई लाइसेंसी;

(३) "विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता" से अभिप्रेत है ऐसा सेवा प्रदाता जिसे उसके लाइसेंस के निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत घरेलू लीज्ड सर्किटों के प्रावधान के लिए प्रत्यक्ष रूप से सब्सक्राइबरों को एक्सेस करने की अनुमति दी गई है;

(४) इन विनियमों में प्रयुक्त किए परंतु परिभाषित नहीं किए गए तथा अधिनियम में तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में और अन्य विनियमों में परिभाषित किए अन्य सभी शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें, यथास्थिति, क्रमशः अधिनियम में अथवा नियमों अथवा अन्य विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

### अध्याय III

#### घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड के प्रावधान से संबंधित पद्धति

4. घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड के प्रावधान के लिए अनुरोधः (१) कोई निर्दिष्ट सेवा प्रदाता,—

(क) जिसका किसी ठेके के अंतर्गत अपने सब्सक्राइबरों के प्रति कोई दायित्व है अथवा जिसके पास अपने सब्सक्राइबरों के साथ घरेलू लीज्ड सर्किटों का प्रावधान करने की कोई अन्य व्यवस्था है; तथा

(ख) जिसके पास इसे ऐसे ठेके अथवा व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान करने हेतु इसके लिए पर्याप्त घरेलू लीज्ड सर्किट अथवा संसाधन नहीं हैं,

वह, यथास्थिति, घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की लोकल लीड प्रदान करने के लिए किसी अन्य विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता को लिखित में अनुरोध करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत अनुरोध करने वाला प्रत्येक सेवा प्रदाता, ऐसा अनुरोध करते समय, अन्य विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता को, ऐसे अनुरोध के साथ, उससे अर्जित किए जाने वाले, यथास्थिति, घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड से संबंधित निम्नलिखित विवरण सूचित करेगा अर्थात्:—

- (क) विनिर्दिष्ट स्थान, जिनके बीच, यथास्थिति, घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड अपेक्षित है;
- (ख) अर्जित किए जाने वाले सर्किटों की संख्या;
- (ग) अर्जित किए जाने वाले, यथास्थिति, घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किटों की स्थानीय लीड के पट्टे की अवधि;
- (घ) अर्जित किए जाने वाले घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड से संबंधित तकनीकी जानकारी (इसके प्रकार, क्षमता अथवा बैंडविड्थ सहित);
- (ङ) अन्य संगत विवरण।

5. घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किटों की स्थानीय लीड प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता, जिसको विनियम 4 के अंतर्गत अनुरोध किया गया है, का दाखिल: (1) विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता, जिसे, यथास्थिति, घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किटों की स्थानीय लीड के प्रावधान के लिए विनियम 4 के अंतर्गत अनुरोध किया गया है, ऐसे अनुरोध के प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर, विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता, जिसने ऐसा अनुरोध किया है (जिसे इसके पश्चात् अनुरोधकर्ता विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता कहा गया है), को निम्नलिखित भेजेगा,—

- (क) यथास्थिति, घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड प्रदान करने की इसकी समर्थता की पुष्टि;
- (ख) एक मांग-पत्र, जिसमें संगत विवरण (प्रभार एवं भुगतान अनुसूची सहित) होंगे, यदि विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता, जिसे विनियम 4 के अंतर्गत अनुरोध किया गया है, यथास्थिति, घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड को प्रदान करने की अपनी समर्थता की पुष्टि करता है;

(ग) यथास्थिति, घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड प्रदान करने के लिए भुगतान अनुसूची के विवरण;

(घ) विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता द्वारा, यथास्थिति, घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड के प्रावधान करने की संभावित तारीख।

(2) यदि विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता, जिसे विनियम 4 के अंतर्गत अनुरोध किया गया है, के लिए क्षमता की अनुपलब्धता अथवा तकनीकी गैर-व्यवहार्यता के कारण अनुरोधकर्ता विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता को, यथास्थिति, घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है, तो विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात तीस दिन के भीतर इसके कारणों का उल्लेख करते हुए इसे लिखित में अनुरोधकर्ता विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता को सूचित करेगा।

6. कृतिपय मामलों में अभिलेखों का अनुरक्षण: यदि कोई विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता, जिसे, यथास्थिति, घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड प्रदान करने के लिए विनियम 4 के अंतर्गत अनुरोध किया गया है, यथास्थिति, घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड उपलब्ध कराने में असमर्थ है तथा वह इसके कारणों को अनुरोधकर्ता विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता को सूचित करता है, तो सेवा प्रदाता, जिसे विनियम 4 के अंतर्गत अनुरोध किया गया है, ऐसे प्रत्येक मामले के अभिलेख का अनुरक्षण करेगा जिसमें उसके कारणों का उल्लेख किया गया होगा तथा ऐसे अभिलेख ऐसी सूचना की तारीख से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि हेतु ऐसे सभी मामलों के लिए अनुरक्षित किए जाएंगे।

### अध्याय III

#### घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड के प्रावधान के लिए दरें

7. घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड के लिए टैरिफ़: (1) इन विनियमों के अधीन [विनियम (2) तथा विनियम (8) के अंतर्गत पड़ने वाले ऐसे मामलों के अलावा] एक विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता द्वारा दूसरे विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता को प्रदान किए गए, यथास्थिति, घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड के लिए दरें वे होंगी, जैसीकि, यथास्थिति, दूरसंचार टैरिफ़ आदेश, 1999 की अनुसूची-IV के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई है, अथवा, जैसीकि अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की गई हैं।

(2) यदि उप-विनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड के लिए दरें दूरसंचार टैरिफ़ आदेश, 1999 की अनुसूची-IV के अंतर्गत, अथवा, अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित नहीं की गई हैं, तो ऐसे मामले में, किसी निर्दिष्ट सेवा प्रदाता द्वारा अन्य निर्दिष्ट सेवा प्रदाता को, इन विनियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड के लिए दरें ऐसी होंगी, जो ऐसे सेवा प्रदाताओं के बीच पारस्परिक सहमति से नियत की जाएं।

8. “किराया और गारंटी निबंधनों” अथवा “विशेष संविदात्मक निर्माण आधार” अथवा कुछ मामलों में “अंशदान आधार” पर घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड के लिए प्रावधान: (1) यदि विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता, जिसे विनियम 4 के अंतर्गत अनुरोध किया गया है,—

(क) क्षमता की अनुपलब्धता अथवा तकनीकी गैर-व्यवहार्यता के कारण से अनुरोधकर्ता विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता, जिसने ऐसा अनुरोध किया है, को यथास्थिति, घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड प्रदान करने में असमर्थ है;

(ख) विनियम 5 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत अनुरोधकर्ता विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता को इसके कारण सूचित करता है,

तो विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता, जिसे विनियम 4 के अंतर्गत अनुरोध किया गया है, अनुरोधकर्ता विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता को, यथास्थिति, घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड "किराए और गारंटी निबंधनों" अथवा "विशेष निर्माण आधार" अथवा "अंशदान आधार" पर अर्जित करने का विकल्प देगा, जैसेकि यह इसके द्वारा अनुरोधकर्ता विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता को प्रदान किए गए हों।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता जिसे विनियम 4 के अंतर्गत अनुरोध किया गया है,—

(क) उप-विनियम (1) के अंतर्गत विकल्प देने के पश्चात;

(ख) अनुरोधकर्ता विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता, जिसे उप-विनियम (1) के अंतर्गत, यथास्थिति, "किराया और गारंटी निबंधनों" अथवा "विशेष निर्माण आधार" अथवा "अंशदान आधार" पर, यथास्थिति, घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड प्रदान करने का विकल्प दिया गया है, से पुष्टि प्राप्त होने पर;

(ग) अनुरोधकर्ता विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता से अपेक्षित भुगतान की प्राप्ति पर,

अनुसोधकर्ता विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता को, उनके बीच हुई सहमति के अनुसार, "किराया और गारंटी निबंधनों" अथवा "विशेष निर्माण आधार" अथवा "अंशदान आधार" पर, यथास्थिति, घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड प्रदान करेगा।

(3) दूरसंचार टैरिक आदेश, 1980 की अनुसूची-IV में अंतर्विष्ट कोई भी बात उप-विनियम (2) के अंतर्गत मिर्दिष्ट उनके बीच यथासहमत "किराया और गारंटी निबंधनों" अथवा "विशेष निर्माण आधार" अथवा "अंशदान आधार" पर प्रदान किए गए, यथास्थिति, घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड पर लागू नहीं होगी।

#### अध्याय IV

### घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड से संबंधित सुरक्षा

७. घरेलू लीज्ड सर्किटों के संबंध में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्थाएं (विधिसम्मत अवरोधन सहित): (1) कोई विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता, जो संसाधनों का स्वामी है तथा सब्सक्राइबरों को घरेलू लीज्ड सर्किट प्रदान करता है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि तथा इसके लाइसेंस के निबंधन और शर्तों अथवा सरकार या इसके किसी प्राधिकरण या एजेंसी द्वारा जारी किसी अन्य निदेश अथवा ऐसे सब्सक्राइबर की किसी देयता के प्रति पूर्वापेक्षा रखे बिना,—

(क) इस प्रकार प्रदान किए गए इसके घरेलू लीज्ड सर्किट सर्किटों के सदाशयी प्रयोग के लिए उत्तरदायी होगा तथा इसके किसी दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) सब्सक्राइबर को इस प्रकार प्रदान किए गए घरेलू लीज्ड सर्किटों के लिए सुरक्षा और निगरानी व्यवस्थाओं (विधिसम्मत अवरोधन सहित) के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) कोई प्रमुख सेवा प्रदाता, जो,—

(क) एंड-टु-एंड घरेलू लीज्ड सर्किट अथवा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अथवा क्लोज्ड यूजर ग्रुप का निर्माण करता है,

(ख) उक्त प्रयोजन के सब्सक्राइबर को घरेलू लीज्ड सर्किटों को प्रदान करने के प्रयोजनार्थ एक या अधिक विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाताओं के घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड का उपयोग करता है,

तो वह, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और लाइसेंस के निबंधन एवं शर्तों अथवा सरकार या इसके किसी प्राधिकरण या एजेंसी द्वारा जारी किसी अन्य निदेश अथवा ऐसे विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा अधिक सेवा प्रदाता की देयता के प्रति पूर्वापेक्षा रखे बिना,—

(i) इस प्रकार प्रदान किए गए, यथास्थिति, इसके घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड के सदाशयी प्रयोग के लिए उत्तरदायी होगा तथा उसके किसी दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी होगा;

(ii) घरेलू लीज्ड सर्किटों की सुरक्षा और निगरानी (विधिसम्मत अवरोधन सहित) व्यवस्थाओं के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) यदि कार्ड सब्सक्राइबर लीज्ड सर्किट अथवा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अथवा क्लोज्ड यूजर ग्रुप का निर्माण करने के लिए एक या अधिक विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाताओं से संसाधनों को प्राप्त करता है, तो ऐसे मामले में, ऐसे सब्सक्राइबर के साथ करार रखने वाले ऐसे सभी दो या अधिक विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता, प्रमुख सेवा प्रदाता होंगे, तथा वे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और ऐसे सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस के निबंधन और शर्तों अथवा सरकार या इसके किसी प्राधिकरण या एजेंसी द्वारा जारी अन्य किसी निदेश अथवा ऐसे सब्सक्राइबर की किसी देयता के प्रति पूर्वापेक्षा रखे बिना,

(क) यथास्थिति, उनके घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड के सदाशयी प्रयोग के लिए अलग—अलग अथवा संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे और उसके दुरुपयोग के लिए अलग—अलग अथवा संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे;

(ख) ऐसे सब्सक्राइबरों को प्रदान किए गए घरेलू लीज्ड सर्किटों (विधिसम्मत अवरोधन सहित) के लिए सुरक्षा और निगरानी व्यवस्थाओं के लिए अलग—अलग अथवा संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

## अध्याय V

### प्रकीर्ण

10. इन विनियमों का कठिपय मामलों में लागू न होना: इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बातं निम्नलिखित में से किसी पर लागू नहीं होगी—

(क) कोई मामला अथवा मुददा जिसके लिए किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के समक्ष अथवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत कोई कार्यवाही लंबित हो; अथवा

(ख) कोई मामला अथवा मुददा, जिसके लिए, यथास्थिति, किसी सकाम न्यायालय अथवा अधिकरण अथवा प्राधिकरण अथवा फोरम अथवा आयोग द्वारा कोई डिक्री, पंचाट अथवा कोई आदेश पहले ही पारित कर दिया है;

(ग) इन विनियमों के आरंभ होने से पूर्व, यथास्थिति, घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड के प्रावधान से संबंधित किया गया करार।

11. बाधित न की गई अन्य विधियों का लागू होना: इन विनियमों के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, उनके अल्पीकरण में नहीं।

12. **निरीक्षण और लेखापरीक्षा:** (1) प्राधिकरण, यदि ऐसा करना आवश्यक समझे और इन विनियमों के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, लिखित में आदेश द्वारा, अपने अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को निदेश देकर अथवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त एक अथवा अधिक व्यक्तियों के माध्यम से उप-विनियम (8) के अधीन अनुरक्षित किसी अभिलेख की जांच करा सकेगा तथा ऐसे निरीक्षण के संबंध में एक रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

(2) प्राधिकरण, यदि वह ऐसा आवश्यक समझे, किसी विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता से, जिसे विनियम 4 के अंतर्गत अनुरोध किया गया है, निम्न करने की अपेक्षा कर सकेगा कि वह—  
 (क) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए एक अथवा अधिक अधिकारियों द्वारा विनियम 6 के अंतर्गत अनुरक्षित अभिलेखों की लेखापरीक्षा कराए और ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करे;  
 (ख) प्राधिकरण द्वारा यथानिर्दिष्ट किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से विनियम 6 के अंतर्गत अनुरक्षित अभिलेखों की लेखापरीक्षा कराए तथा ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करे।

(3) उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा नियुक्त एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण अथवा उप-विनियम (2) के खंड (ख) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की लागत का वहन संबंधित विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा।

(4) प्राधिकरण, आदेश अथवा निदेश द्वारा, समय-समय पर, सब्सक्राइबरों अथवा विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाताओं के हितों के संरक्षण के लिए अथवा इन विनियमों के अंतर्गत, यथास्थिति, घरेलू लीज्ड सर्किटों अथवा घरेलू लीज्ड सर्किट की स्थानीय लीड का प्रावधान सुनिश्चित करने और उसकी निगरानी के प्रयोजन के लिए हस्तक्षेप कर सकेगा ताकि दूरसंचार क्षेत्र का संवर्धन तथा व्यवस्थित विकास सुनिश्चित हो सके।

लव गुप्ता, प्रधान सलाहकार (एफएन)  
 [विज्ञापन-III/IV/असा./142/07]

**टिप्पणी :**— व्याख्यात्मक ज्ञापन घरेलू लीज्ड सर्किट विनियम, 2007 के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है।

**घरेलू लीज्ड सर्किट विनियम, 2007 (2007 का 10) का**  
**व्याख्यात्मक ज्ञापन**

**1. अस्तावना**

1.1 आमतौर पर लीज्ड सर्किट एक प्रकार की सुविधा है जिसका प्रयोग एक ग्राहक अनन्य रूप से दो या अधिक एन अभिहित बिन्दुओं के बीच संप्रेषण के लिए करता है। इसे एक या अधिक एक्स्ट्राइंट-ट्रु-प्वाइंट कनेक्शन या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के रूप में एक सांझा नेटवर्क पर स्थापित किया जा सकता है। सार्वजनिक स्विच्च नेटवर्क को लीज्ड नेटवर्क के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह सुविधा एक सेवा प्रदाता द्वारा प्रचलित या उसके स्वामित्व वाली सुविधाओं या दूसरे सेवा प्रदाता द्वारा बेची गई या पट्टे पर दी गई ट्रांसमिशन क्षमता पर उपलब्ध कराई जाए। यह स्थलीय अथवा उपग्रह सुविधाओं, किसी मीडिया, कॉपर, फाइबर अथवा वायरलैस का प्रयोग करे और इसे निष्क्रिय, सर्किट, स्विच्च या पैकेट स्विच्च नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। लीज्ड सर्किट में केन्द्रीय कार्यालय स्विचिंग ऑपरेशन शामिल नहीं है। ब्रॉडबैंड से भिन्न, एक लीज्ड लाइन आशयित अथवा सांझा नहीं है अपितु यह समर्पित गारंटीशुदा बैडविक्स्यूथ प्रदान करती है।

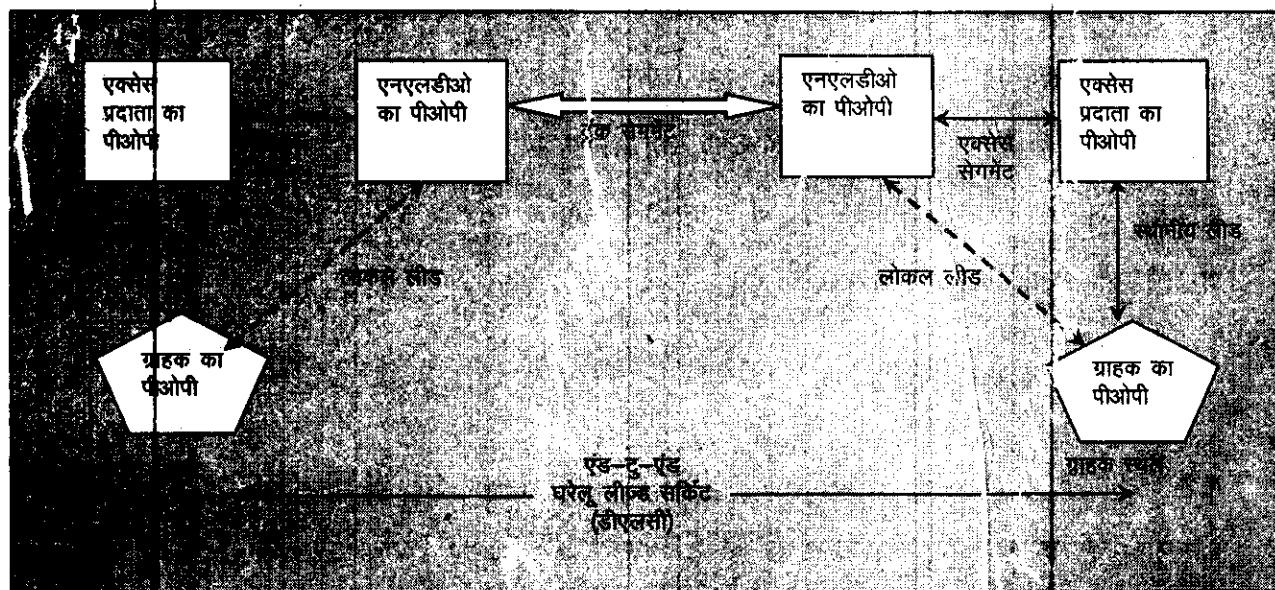
1.2 आईटीयू लीज्ड सर्किट को “किसी सब्सक्राइबर के अनन्य प्रयोग हेतु एक दोतरफा संपर्क है चाहे सब्सक्राइबर इसका प्रयोग किसी भी तरीके से करे .....” के रूप में परिभाषित करता है।

1.3 घरेलू लीज्ड सर्किट (डीएलसी) दूरसंचार बाजार के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो दूरसंचार सेवा प्रदाता दो या दो से अधिक ग्राहक स्थलों या ग्राहकों को अपने या दूसरे सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क से जोड़ने के लिए उपलब्ध कराता है।

1.4 एक एंड-टु-एड घरेलू लीज्ड सर्किट (डीएलसी) के विभिन्न तत्वों में निम्नलिखित सेंगमेंट शामिल हैं:—

- (क) स्थानीय लीड (एक्सेस प्रदाता या राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक का निकटतम प्वाइंट ऑफ प्रिजेंस (पीओपी) / अंतरसंयोजन बिंदु (पीओआई)
- (ख) एक्सेस सेगमेंट
- (ग) ट्रांक सेगमेंट

एक घरेलू लीज्ड सर्किट (डीएलसी) के विभिन्न तत्वों को बताने वाला योजनावार चित्र नीचे दिया गया है:—



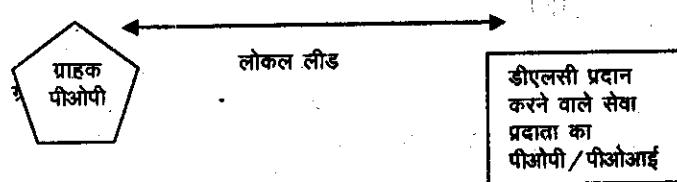
एनएलडीओ: राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक

पीओपी: प्वाइंट ऑफ प्रिजेंस

चित्र-1 घरेलू लीज्ड सर्किट (डीएलसी) का योजनावार चित्र

1.5 स्थानीय लीड डीएलसी का एक अनिवार्य भाग है। इसका टर्मिनेटिंग सेगमेंट, पार्श्वियल सर्किट, टेल एंड, लोकल एंड या स्थानीय लीज्ड सर्किट के रूप में भी उल्लेख किया गया है। ऐसे दृष्टांतों में, जहां पर स्थानीय लीड कॉपर लिंक की बनी है, इसे प्रायः एक लोकल लूप के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रकार का ग्राहक के परिसर से नेटवर्क प्रचालक के प्वाइंट ऑफ प्रिजेस (पीओपी) या अंतरसंयोजन बिंदु (पीओआई) तक एक लीज्ड सर्किट है जिससे ग्राहक लीज्ड लाइन क्षमता प्राप्त करता है। स्थानीय लीड, डीएलसी के प्रावधान हेतु ग्राहक से करार करने वाले किसी सेवा प्रदाता से भिन्न सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई जाए।

1.6 स्थानीय लीड, सेवा प्रदाता के एक्सेस नेटवर्क का एक भाग है यह विविध रूप में हो सकता है: टेलीफोन ग्राहक के लिए यह सुख्यतः कॉपर पेयर हो, ब्रॉडबैंड प्रयोक्ताओं के लिए यह कॉपर पेयर या फाइबर के रूप में हो सकती है, इंटरप्राइज ईपीएबीएक्स जो जोड़ने के लिए यह कॉपर या फाइबर के रूप में हो, लीज्ड लाइन के लिए यह कॉपर, फाइबर या वायरलैस के रूप में हो।



## चित्र 2 स्थानीय लीड को दर्शाने वाला योजनावार चित्र

1.6 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का उद्देश्य भी वही है जो वास्तविक लीज्ड सर्किट का है। वीपीएन, बड़े नेटवर्क की स्केल और प्रबंध सुविधाओं की अर्थशास्त्रीयता का लाभ उठाने हेतु एक सार्वजनिक नेटवर्क (एक कैरियर नेटवर्क या इंटरनेट) के भीतर संरूप है। अतः अधिकांश मौकों पर वीपीएन, लीज्ड लाइनों के रूप में उन्हीं क्षमताओं वाला किंतु काफी कम लागत पर एक प्रयोक्ता संगठन उपलब्ध कराता है। हालांकि एक वीपीएन आमतौर पर सांझा सार्वजनिक अवसंरचना का प्रयोग करके

बनाया जाता है, सुरक्षा प्रक्रियाओं और टनलिंग प्रोटोकोल के माध्यम से निजता और सुरक्षा रखी जाती है। प्रेषक छोर पर डाटा इंक्रिप्ट करके और प्राप्ति छोर पर डाटा डिक्रिप्ट करके प्रोटोकोल का प्रयोग किया जाता है और एक 'टनल' के माध्यम से डाटा भेजा जाता है जिसे पर्याप्त रूप से इंक्रिप्ट डाटा द्वारा 'एंटर' नहीं किया जा सकता है। सुरक्षा के अपर स्तर पर न केवल डाटा को इंक्रिप्ट करना अपितु उत्पत्ति करने वाले और प्राप्त करने वालों को भी शामिल करना है।

वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन का प्रयोग इंटरप्राजिज द्वारा शाखा कार्यालयों को साइट-टु-साइट कनेक्शन प्रदान करने और टेलीकम्यूटरों को अपनी कंपनी का एलएएन डायल करने की अनुमति देने हेतु वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) सृजित करने हेतु किया जाता है जिसमें बड़े भौगोलिक क्षेत्र शामिल हैं।

### 1.8 डीएलसी और वीपीएन सेगमेंट में सेवा प्रदाता

1.8.1 आज की तारीख के अनुसार, देश में विभिन्न श्रेणी के प्रचालकों द्वारा अंतिम प्रयोक्ताओं को घरेलू बैंडविड्थ प्रदान की जाती है:-

- क) राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक (एनएलडीओ)
- ख) एक्सेस सेवा प्रदाता (बीएसओ / यूएएसपी)

1.8.2 दूरसंचार विभाग (डीओटी) के दिनांक 14 दिसम्बर, 2005 के दिशानिदेशानुसार, आईपी-II श्रेणी को अब समाप्त कर दिया गया है और अब कोई नया आईपी-II लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा। अद्यपूर्व आईपी-II कंपनियों को प्रत्येक लाइसेंस के लिए अपेक्षित लाइसेंस फीस का भुगतान करके एनएलडी/आईएलडी सेवा लाइसेंस प्राप्त करने का विकल्प दिया गया था। इसके अतिरिक्त, ऐसे आईपी-II लाइसेंसधारक जो एनएलडी/आईएलडी अपनाने के इच्छुक नहीं हैं, को वर्तमान आईपी-II

दिशानिदेशानुसार, व्यक्तिगत सम्प्रकाशिकरों को राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय लीज्ड लाइन/बैंडविड्थ उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डीओटी के दिनांक 14 दिसम्बर, 2005 के दिशानिदेशानुसार, एनएलडीओ केवल लीज्ड सर्किट/क्लोज यूजर ग्रुप (सीयूजी) के प्रावधान हेतु सम्प्रकाशिकर एक्सेस कर सकते हैं।

### 1.9 लीज्ड लाइन और वीपीएन हेतु मांग

1.9.1 आईडीसी द्वारा आईपी, वीपीएन सेवाओं के विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2003 में घरेलू वीपीएन हेतु बाजार लगभग 216 करोड़ रुपए का था और इसके वर्ष 2006 में बढ़कर 831 करोड़ रुपए होने की आशा है जैसाकि नीचे सारणी-1 में दिखाया गया है:-

भारत आईपी-वीपीएन सेवा बाजार राजस्व पूर्वानुमान, करोड़ रु. में, 2003-2008						
वर्ष	2003	2004	2005	2006	2007	2008
राष्ट्रीय आईपी वीपीएन	215.6	329.5	474.9	586.8	704.1	830.9
अन्तरराष्ट्रीय आईपी वीपीएन	14.7	32.9	61.5	108.3	186.4	310.3

स्रोत: आईडीसी रिपोर्ट, 2003

### सारणी-1

फ्रोस्ट एंड सुलिवन द्वारा किए गए ऐसे ही विश्लेषण में लगभग समान राजस्व पूर्वानुमान दर्शाया गया है:-

## आईपी वीपीएन बाजार: राजस्व पूर्वानुमान (भारत), 2003—2009

वर्ष	राजस्व	राजस्व
	(करोड़ रु. में)	वृद्धि दर
2003	226.80	
2004	281.70	24.1
2005	387.90	37.6
2006	508.50	31.5
2007	672.30	32.0
2008	894.60	33.1
2009	1198.35	33.9

आईपीवीएन बाजार: राजस्व पूर्वानुमान (भारत), 2003—2009, स्रोत: फ्रॉस्ट एंड सुलिवन

सारणी—2

1.9.2 “आईएसपी लाइसेंस तथा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) संबंधी मुददे” पर द्राई के दिनांक 24 जून, 2005 के परामर्श—पत्र में प्वाइंट-टु-प्वाइंट लीज्ड लाइन बाजार के वर्ष 2006—2007 तक 1400 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है।

## घरेलू लीज्ड सर्किट से उद्भूत राजस्व (करोड़ रु. में)

वित्त वर्ष	वास्तविक राजस्व		अनुमानित राजस्व		
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राजस्व (करोड़ रु. में)	577	783.52	901.05	1081.26	1405.63

स्रोत: आईएसपी लाइसेंस तथा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) संबंधी मुददों पर द्राई का दिनांक 24 जून, 2005 तक परामर्श—पत्र

सारणी—3

1.9.3 बुनियादी/एकीकृत एक्सेस लाइसेंस और राष्ट्रीय लंबी दूरी लाइसेंस के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं द्वारा बताया गया प्वाइंट-टु-प्वाइंट लीज्ड लाइन राजस्व वर्ष 2004—05 और 2005—06 के लिए क्रमशः 905 करोड़ रुपए तथा 1291 करोड़ रुपए है। यह नोट

किया गया है कि इस राशि में इंटरनेट लाइसेंस के अंतर्गत वीपीएन सेवाओं से सृजित राजस्व शामिल नहीं है। अतः घरेलू लीज्ड सर्किट बाजार काफी तेजी से बढ़ रहा है।

1.9.4 उपलब्ध डाटा के अनुसार समग्र डीएलसी बाजार (वीपीएन सहित) के वर्ष 2008 तक 3000 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2010 तक 4500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

1.10 अर्थव्यवस्था के लिए डीएलसी का महत्व: लीज्ड लाइनें देश की आर्थिक वृद्धि के लिए एक प्रमुख घटक बनी हुई हैं और रहेंगी। इसके अतिरिक्त, ये लाइनें ई-बिजनेस, ई-गर्वनेंस, इंटरनेट एक्सेस, बीपीओ और आईटी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण निर्माण ब्लॉक हैं। वित्तीय, आईटीईएस और विनिर्माण क्षेत्र के आईपी वीपीएन बाजार वृद्धि में अग्रणी भूमिका निभाने की आशा है। वित्तीय क्षेत्र में बैंक अपने ब्रांच नेटवर्क को स्वचालित बनाने तथा छोट शहरों तक विस्तार कर रहे हैं। इन ब्रांचों को जोड़ने के लिए वीपीएन का विकास करना होगा। वीपीएन को वीएसएटी की तरह प्वाइंट-टु-प्वाइंट कनेक्शन का एक सर्वाधिक किफायती विकल्प माना जा रहा है। वर्ष 2003-2009 की अवधि में भारतीय आईपी वीपीएन सेवाओं में वर्टिकल सेगमेंट का रूप “भारतीय आईपी वीपीएन बाजार हेतु बाजार इंजीनियरी अनुसंधान” संबंधी फ्रोस्ट एंड सुलिवन रिपोर्ट में भी दिया गया है।

आईपी वीपीएन बाजार: वर्टिकल सेगमेंट (इंडिया) द्वारा रख; 2003-2009							
वर्टिकल बाजार	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
एफएमसीजी	35	25	20	20	20	15	15
हेल्थकेयर	25	20	20	20	25	20	20
दूरसंचार/आईटी/उच्च प्रौद्योगिकी	31	31	30	25	20	20	20
बैंक	0	7	10	15	15	20	20
सरकार	5	5	5	5	5	10	10
शिक्षा	0	7	8	8	10	10	10
अन्य	5	5	7	7	5	5	5
आईपीवीएन बाजार: 2003-2009 का पूर्णानुमान स्रोत: फ्रोस्ट एंड सुलिवन							

1.11 सामान्यतया लीज्ड लाइनों का प्रयोग उन कारोबारियों द्वारा किया जाता है जिन्हें एसएलए (सर्विस लेवल एग्रीमेंट) के साथ अलग—अलग कार्यालयों के लिए उच्च व्यालिटी का 27/7 अंतरसंयोजन की जरूरत हो ताकि द्रुत अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम गति या इंटरनेट एक्सेस सहित महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को चलाया जा सके। उदाहरण के लिए कम कर्मचारी वाले एसेसिंग कार्यालय आधारित अनुप्रयोग, अपने कार्यालय डाटाबेस से समृद्ध मल्टीमीडिया डाटा पुनः प्राप्त करेंगे जिसके लिए उच्च डाउनस्ट्रीम बैंडविड्थ की जरूरत होगी। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (केपीओ)/कंपनियों और मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने वाले कारोबारियों को शायद ज्यादा डाटा अपलोड करने के लिए उच्च अपस्ट्रीम बैंडविड्थ की जरूरत होगी। इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) भी लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस के प्रावधान हेतु अपने ग्राहकों को अपने नोड से जोड़ने के लिए डीएलसी का प्रयोग कर सकते हैं। अतः नए कारोबारियों और सेवा प्रदाताओं के लिए डीएलसी एक्सेस एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

1.12 सरकार द्वारा प्रवेश बाधाओं और देय लाइसेंस फीस में कटौती करने जैसी कुछ नीतिगत पहलों से उद्भूत उभरती प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर तथा सेवा के क्षेत्र में वृद्धि अर्थात् एनएलडीओ को लीज्ड सर्किट/क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयूजी) के प्रावधान हेतु सीधे सब्सक्राइबर के एक्सेस की अनुमति देने, कई कंपनियों के प्रवेश तथा बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक दबाव, आईपी वीपीएन बाजार सहित घरेलू लीज्ड सर्किट बाजार के आगामी वर्षों में एक स्वस्थ दर पर वृद्धि करने की संभावना है।

1.13 सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने अंतिम प्रयोक्ताओं को प्रदान की गई दूरसंचार सेवाएं मुख्यतः ऐसे लीज्ड सर्किट की गुणवत्ता और समय पर उपलब्धता पर निर्भर करती है। एंड-टु-एंड कनेक्टिविटी के सभी सेगमेंट की आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा, प्रयोक्ताओं को एक उचित मूल्य पर खुदरा उत्पादों की आपूर्ति हेतु महत्वपूर्ण है। नए प्रवेशकर्ता प्रायः डीएलसी के हिस्सों विशेष रूप से एक्सेस हिस्सों की अनुपलब्धता के कारण घरेलू लीज्ड लाइन बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई महसूस करते हैं। प्राधिकरण का

यह मत है कि ग्राहक में अपनी इच्छा को सीमित करने वाली अवास्तविक तथा प्रतिस्पर्धा रोधी बाधाओं के बिना डीएलसी के अपने वरीयता प्राप्त सेवा को चुनने की क्षमता होनी चाहिए जैसाकि वे दूरसंचार क्षेत्र के अन्य सेगमेंट में करते हैं।

1.14 आज के बहु-प्रचालक, बहु-सेवा परिदृश्य में एक्सेस शब्द के कई अर्थ हैं। प्राधिकरण यह मानता है कि बाजार में जहां कुछ सेवा प्रदाता, अपनी सेवाओं की आपूर्ति के लिए दूसरों द्वारा उपलब्ध कराई गई अनिवार्य सुविधाओं पर निर्भर हैं, एक ढांचा स्थापित करना उपर्युक्त होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बाजार प्रभावी रूप से काम करे।

1.15 उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकरण का यह मत है कि सेवा प्रदाता स्थानीय लीड के संदर्भ में डीएलसी या एक्सेस को पूरा करने के अन्य सेवा प्रदाताओं के अनुरोध को पूरा करे क्योंकि सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे अनुरोध को मानने से इंकार करने या अतार्किक शर्त रखने और ऐसे ही प्रभाव वाले अन्य निबंधनों को पेश करने से प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के प्रादुर्भाव में बाधार आएगी या यह अंतिम प्रयोक्ताओं के हित में नहीं होगा। अतः प्राधिकरण ने काफी सचेतना के बाद इन विनियमों को जारी करने का निर्णय लिया है।

1.16 ये विनियम पारदर्शिता, भविष्यवाणी और युक्तियुक्तता को सुनिश्चित करने तथा गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से डीएलसी/स्थानीय लीड का प्रावधान करने की अनुमति देने हेतु एक ढांचा उपलब्ध कराते हैं। प्राधिकरण ने अनिवार्य आदेश का विकल्प नहीं चुना है अपितु वह भविष्य में स्थिति की मांग के अनुसार इस पर निगरानी रखेगा और आवश्यक कदम उठाएगा।

1.17 ये विनियम विशेष रूप से घरेलू लीज्ड सर्किट के लिए हैं और यह मानते हैं कि एक्सेस डीएलसी बनाने हेतु एक अनिवार्य अंग है, अतः सेवा प्रदाताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अन्य सेवा प्रदाताओं के अनुरोध पर न केवल डीएलसी अपितु ऐसे मामलों में एक्सेस नेटवर्क के लिए स्थानीय लीड को छोड़कर शेष डीएलसी का निर्माण कर सकता है।

1.18 डीएलसी और/या स्थानीय लीड उपलब्ध कराते समय, सेवा प्रदाताओं का यह दायित्व है कि वे समान सेवाएं उपलब्ध कराने वाले अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए भी समान शर्तें लागू करें और उन्हीं शर्तों पर सेवाएं उपलब्ध कराए और उसकी गुणवत्ता भी वैसी ही हो जो वह अपने ग्राहकों को प्रदान कर रहा है जब तक कि इस प्रावधान के विभिन्न निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करने वाले विशिष्ट एसएलए न हो।

1.19 परामर्श प्रक्रिया: घरेलू लीज्ड सर्किट (डीएलसी) में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, प्राधिकरण ने नवम्बर, 2006 में एक परामर्श—प्रक्रिया शुरू की और दिनांक 17 नवम्बर, 2006 को “भारत में बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उपाय” पर एक परामर्श—पत्र जारी किया। इस विषय पर 29 जनवरी, 2007 को दिल्ली में एक ओपन हाउस चर्चा भी की गई।

1.20 प्राधिकरण ने दिनांक 17 नवम्बर, 2006 के अपने परामर्श—पत्र में देश के घरेलू लीज्ड सर्किट (डीएलसी) बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न मुददों पर प्रकाश डाला। प्राधिकरण द्वारा परामर्श—पत्र में निम्नलिखित मुददे उठाए गए थे:

- डीएलसी बाजार में प्रतिस्पर्धा हेतु सीमित कारक
- क्या विशिष्ट बाजार शक्ति (एसएमपी) वाले प्रचालक को डीएलसी के लिए और अन्य प्रचालकों को सीयूजी संपर्क के लिए भी स्थानीय लीड उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाए।

- iii) सुरक्षा संबंधी मुद्दों के लिए जिम्मेदारी
- iv) क्या एक अंतरसंयोजन तत्व के रूप में डीएलसी के प्रावधान पर विचार किया और इसे संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) में शामिल किया जाए।
- v) डीएलसी बाजार में प्रभावी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के अन्य उपाय।

## 2. पण्धारकों द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियों तथा उठाए गए मुद्दों की जांच

2.1 प्राधिकरण ने पण्धारकों की विभिन्न टिप्पणियों और उनकी रायों पर विचार किया है तथा मामले का विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया है। स्पष्टता की दृष्टि से, पण्धारकों द्वारा की गई टिप्पणियों तथा उठाए गए मुद्दों को तिरछी टाइप में दिया गया है तथा उसके बाद उन बिंदुओं पर प्राधिकरण द्वारा किए गए विचार व निर्णय का विवरण दिया गया है।

### 2.2 मुद्दा 1: डीएलसी बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए सीमितकारी कारक

2.2.1 इस मुद्दे पर पण्धारकों से प्राप्त टिप्पणियां नीचे बिंदु (क) से (ड) में दी गई हैं तथा उसके बाद के पैराओं में उन पर चर्चा की गई है।

- (क) लीज्ड सर्किट बाजार में प्रतिस्पर्धा सीमित नहीं है।
- (ख) प्रतिस्पर्धा ने अपेक्षा की है कि प्रतिस्पर्धा प्रचालकों को पर्याप्त अवसरंचना का निर्माण करना चाहिए।
- (ग) निजी प्रचालकों के सेवा क्षेत्र के सभी भागों में अवसरंचना विकास के प्रति उनकी इच्छा शक्ति का अभाव है।
- (घ) निजी प्रचालकों को उपभोक्ताओं को विकल्प देने में समर्थ बनाने के लिए उनके स्वयं के नेटवर्क क्रियान्वित करने के लिए अधिदेशित करना चाहिए।

- (अ) इंकमबेंट्स के साथ संसाधनों की साझेदारी
- (ब) इंकमबेंट अपनी क्षमता की साझेदारी लास्ट भील के लिए नहीं करना चाहते हैं।
- (छ) आरओडब्ल्यू प्राप्त करने में कठिनाइयां तथा उसकी लागत।
- (ज) डीएलसी अवयवों के लिए कीमतें, वितरण की समय—सीमा।
- (झ) कॉपर बिछाने की उच्च लागत तथा कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं।
- (म) माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम शुल्क को औचित्यसम्मत बनाया जाना
- (ट) अंतरसंयोजन विनियमों का अभाव।
- (छ) ग्रामीण क्षेत्रों में डीएलसी के लिए सरकारी नीति।
- (ड) यह अधिदेशित करना चाहिए कि एक प्रचालक दूसरे प्रचालक को डीएलसी अथवा सीयूजी के लिए स्थानीय लीड प्रदान करे।

2.2.2 उक्त टिप्पणियों के साथ, प्राधिकरण ने उन अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा है जो डीएलसी बाजार में प्रतिस्पर्धा को सीमित करने के लिए उत्तरदायी थे। प्राधिकरण ने इस विषय पर सरकार को समय—समय पर दी गई सिफारिशों का भी स्मरण कराया है। सरकार ने या तो स्वयं अपनी ओर से अथवा प्राधिकरणों की सिफारिशों का भी स्मरण किया है। सरकार ने या तो स्वयं अपनी ओर से अथवा प्राधिकरणों की सिफारिशों के आधार पर निर्णय भी लिए हैं जिनके परिणामस्वरूप कुछ अवरोधों को समात करने में सहायता मिली है। कुछ उदाहरण हैं:—

एनएलडी लाइसेंसों के लिए प्रवेश शुल्क में 100 करोड़ रुपए की तुलना में 2.5 करोड़ रुपए की कटौती तथा लाइसेंस शुल्क में 15 प्रतिशत की तुलना में 6 प्रतिशत की कटौती। आईपी-II सेवा प्रदाताओं को एनएलडी लाइसेंस में अंतरित होने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। एनएलडी लाइसेंसी तथा आईपी-II सेवा प्रदाता एनएलडी लाइसेंस में स्थानांतरित होने के पश्चात् सीयूजी हेतु लीज/डाटा सर्किटों के लिए सीधे अपने सब्सक्राइबरों को एक्सेस कर सकते हैं तथा उनसे अपेक्षित है कि वे एंड-टु-एंड संयोजनता के लिए अपने स्वयं के लास्ट भील एक्सेस नेटवर्क का निर्माण करें।

2.2.3 प्राधिकरण का मत है कि प्रतिस्पर्धा को और आगे बढ़ाने के लिए तथा डीएलसी/वीपीएन सेगमेंट की पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए आगे कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस बाजार का दोहन न केवल सेवा प्रदाता तथा देश की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाएगा बल्कि उपभोक्ताओं को डीएलसी/वीपीएन के सेवा प्रदाताओं का चुनाव करने की योग्यता भी प्रदान करेगा। नए प्रवेशकर्ता सामान्यतया डीएलसी के उपांगों, विशेष रूप से एक्सेस उपांग की गैर-उपलब्धता तथा ग्रीनफील्ड क्षेत्रों में नेटवर्क के विस्तार की वित्तीय गैर-व्यवहार्यता के कारण घरेलू लीज्ड लाइन बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई महसूस करते हैं। अतः प्राधिकरण का मत है कि डीएलसी/वीपीएन सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा के शेष रह गए सीमितकारी कारकों को व्यापक रूप से दूर करने के लिए विनियम जारी करने की अविलंब आवश्यकता है।

**2.3 मुद्दा 2: क्या विशेष बाजार शक्ति (एसएमपी) प्राप्त प्रचालक को डीएलसी और अन्य प्रचालकों को सीयूजी से संबंध करने हेतु स्थानीय लीड उपलब्ध कराने हेतु अधिदेशित किया जाए।**

2.3.1 इस मुद्दे पर पण्धारकों से प्राप्त टिप्पणियों को संक्षेप में बिंदु (क) से (घ) तक दिया गया है और तत्पश्चात बाद के पैराओं में इस पर विचार किया गया है।

(क) निजी प्रचालकों के प्रवेश के 10 वर्षों के बाद एसएमपी की संकल्पना प्रासंगिक नहीं है।

(ख) इंकमबैंट सदैव एसएमपी नहीं होता। ऑप्टिकल/मेट्रो इथरनेट और लाभप्रद क्षेत्रों में लंबी दूरी की बैंडविड्थ के मामले में, निजी प्रचालक ही एसएमपी है।

(ग) इंकमबेंट को संसाधनों के अनुलिपिकरण से बचाने हेतु डीएलसी/स्थानीय लीड उपलब्ध कराने हेतु अधिदेशित किया जाए।

(घ) इंकमबेंट को प्रकट तथा पारदर्शी निबंधनों और शर्तों के साथ स्थानीय लीड उपलब्ध कराई जाए।

2.3.2 वर्तमान बाजारी स्थिति और विशेष रूप से एक्सेस नेटवर्क में विभिन्न प्रौद्योगिकियों की तैनाती को देखते हुए, प्राधिकरण यह महसूस करता है कि केवल धुनिंदा सेवा प्रदाताओं के लिए ही इस दायित्व का सीमित करना एक अधोगामी कदम होगा। अतः इस स्तर पर एसएमपी की संकल्पना अधिक प्रासंगिक नहीं है और ऐसे किसी सेवा प्रदाता, जिसके पास कॉपर, फाइबर या वायरलैस की अतिरिक्त क्षमता है, को इसे अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ बांटना चाहिए। सभी सेवा प्रदाताओं की उपलब्ध क्षमता का उपभोक्ताओं के लाभ हेतु पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। प्राधिकरण यह भी आशा करता है कि सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के दीर्घकालीन हिल में नेटवर्क का और आगे विकास करने के काम को भी जारी रखा जाए।

2.3.3 प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि दिनांक 21 अप्रैल, 2005 के "दूरसंचार टैरिफ (छत्तीसवां संशोधन) आदेश, 2005" में पहले से ही यह व्यवस्था है कि जब अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो तो उसके उपयोग के माध्यम से और जब उपलब्ध न हो तो किराए और गारंटी शर्तों/विशेष निर्माण/अंशदान के आधार पर घरेलू लीज्ड सर्किट उपलब्ध कराया जाए। संगत खंड का यहां पुनः उल्लेख किया गया है:—

खंड 2 (ख) "घरेलू लीज्ड सर्किट हेतु यह अनिवार्य है कि इसे अतिरिक्त क्षमता यदि ऐसी क्षमता उपलब्ध हो, के उपयोग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए और यदि यह क्षमता उपलब्ध न हो तो उसे किराए और गारंटी/विशेष निर्माण/अंशदान आदि के आधार पर रिपोर्टिंग आवश्यकता से संबंधित टीटीओ के प्रावधानों के तहत योजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जाए।"

प्राधिकरण का यह मत है कि न केवल डीएलसी अपितु यदि संविदाकारी सेवा प्रदाता और ग्राहक के बीच संविदा या व्यवस्था हेतु स्थानीय लीड की आवश्यकता है तो इसे भी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

2.3.4 प्राधिकरण ने यह भी पाया है कि यद्यपि उल्लिखित टीटीओ में अधिदेश मौजूद है, यदि इन विनियमों के माध्यम से एक ढांचे या कार्यपद्धति को विनिर्दिष्ट किया जाता है तो इसके कार्यान्वयन की गुणवत्ता में भी और अधिक सुधार होगा। सेवा प्रदाताओं के लिए यह भी बाध्यकारी बनाने की जरूरत है कि वह मांगकर्ता को एक निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर डीएलसी/स्थानीय लीड की उपलब्धता या अनुपलब्धता के बारे में सूचित करे। प्रदाता, मांगकर्ता को लिखित में इसके कारणों के बारे में सूचित करे। प्रदाता जिन मामलों में अनुरोध पूरा किया जा सका, उन सभी का रिकॉर्ड भावी संदर्भ हेतु रखेगा।

#### 2.4 मुद्दा 3: सीयूजी नेटवर्क में बहु-सेवा प्रदाताओं से संसाधनों के प्रयोग के मामले में सुरक्षा संबंधी मुद्दों की जिम्मेदारी

2.4.1 इस मुद्दे पर पण्धारकों से प्राप्त टिप्पणियों को संक्षेप में बिंदु (क) से (ज) तक दिया गया है और तत्पश्चात बाद के पैराओं में उन पर विचार किया गया है:

(क) मुख्य सेवा प्रदाता (अधिकांश मामलों में बीएसएनएल) को सुरक्षा मुद्दों के लिए जिम्मेदार ठहराना बहुत ही अनुचित होगा। यह बीएसएनएल पर स्थानीय लीड की अनबंडलिंग पर शास्ति लगाने के साथ-साथ दोहरी शास्ति होगी।

(ख) सेवा प्रदाताओं के बीच विवाद उत्पन्न होंगे और स्थानीय लीड की अनबंडलिंग करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा।

(ग) सुरक्षा संबंधी मुद्दों के मद्देनजर, चूक से सेवा विकृत होने के मामले में समन्वय में कठिनाई होने पर बहु-सेवा प्रदाताओं से संसाधनों का प्रयोग करने की सिफारिश नहीं की जाती है।

(घ) सभी सेवा प्रदाताओं को सुरक्षा संबंधी मुद्दों के लिए जिम्मेदार रहना होगा।

(ङ) मुख्य सेवा प्रदाता सुरक्षा संबंधी मुद्दों के लिए जिम्मेदार है।

(च) सुरक्षा मुद्दों की संपूर्ण जिम्मेवारी, स्वयं सीयूजी के ऊपर ही होनी चाहिए, विशेष रूप से तब यदि ग्राहक बहु-प्रदाताओं से संपर्क प्राप्त करके स्वयं अपना सीयूजी बनाता है।

(छ) यदि ग्राहक वीपीएन जैसी प्रबंधित सेवाओं के लिए प्रमुख सेवा प्रदाता के साथ कोई करार करता है, तो यह प्रमुख सेवा प्रदाता की जिम्मेवारी होनी चाहिए।

(ज) सेवा प्रदाता की खंडवार जिम्मेवार निर्धारित निर्धारित की जानी चाहिए।

2.4.2 इस स्थानीय संसाधिकरण ने नोट किया है कि लाइसेंसर से सीयूजी नेटवर्क स्थापित करने के लिए बहु-लाइसेंसीकृत सेवा प्रचालकों के माध्यम से सीयूजी ग्राहकों द्वारा संसाधनों के उपयोग के बारे में दिनांक 15.07.2003 के अपने पत्र सं0 824-42/200-एलआर द्वारा पहले ही अनुदेश जारी कर दिए हैं। वस्तुतः लीज्ड लाइन के प्रावधान पर कंटेंट समान रूप से लागू हैं जिनमें सर्किट के लंबी दूरी के सेगमेंट को एक प्रचालक द्वारा तथा स्थानीय सेगमेंट को दूसरे के द्वारा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। पहला पैराग्राफ, अन्य बातों के साथ-साथ यह संकेत करता है कि एक लीज्ड लाइन, जिसमें विभिन्न सेगमेंट पर विभिन्न प्रचालकों के सर्किट लिए गए हैं, पूरी तरह अनुमेय है तथा इसके लिए दूरसंचार विभाग से किसी अनुमोदन

अथवा अनुमति की आवश्यकता नहीं है, तथा पश्चात्‌वर्ती पैराग्राफ संकेत करता है कि ऐसा प्रचालकों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत वाणिज्यिक करारों के माध्यम से किया जाना है। इसके अलावा, अंतिम पैराग्राफ यह बताता है कि यह सुनिश्चित करना प्रचालकों की जिम्मेवारी होगी कि दूरसंचार संसाधनों का प्रयोग यथार्थवादी तथा विधिपूर्वक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है।

2.4.3 प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं की इस चिंता को नोट किया है कि इंकमबेंट 'स्थानीय लीड' कनेक्शन तथा उनके ग्राहकों के लीजड सर्किटों के प्रावधान के लिए प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं को आंशिक बिल्ट अप विकल्प प्रदान करने में झिझक रहे हैं, जिसके पीछे उनका तर्क है कि इंकमबेंट को संसाधनों का यथार्थवादी और विधिपूर्वक प्रयोग सुनिश्चित करना है। अतः ये प्रचालक उनके ग्राहकों को एक समुचित/समयबद्ध तरीके से सीयूजी/डाटा नेटवर्कों के लिए संसाधनों के प्रावधान में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने महसूस किया है कि किसी सीयूजी नेटवर्क में बहु—सेवा प्रदाताओं से संसाधनों के प्रयोग के मामले में सुरक्षा संबंधी मुद्दों के लिए जिम्मेदारी को परिभाषित किए जाने की अविलंब आवश्यकता है।

2.4.4 सीयूजी नेटवर्क में बहु—प्रचालक सेवा प्रदाताओं द्वारा संसाधनों के प्रयोग के मामले में सुरक्षा मुद्दों की जिम्मेवारी के बारे में प्राधिकरण का निर्णय है:

सीयूजी नेटवर्क में बहु—सेवा प्रदाताओं से संसाधनों के प्रयोग के मामले में, प्रमुख सेवा प्रदाता, जिसका ग्राहक के साथ करार है तथा जो विभिन्न सेवा प्रदाताओं से संसाधनों का उपयोग करते हुए इसके ग्राहकों को एंड—टु—एंड समाधान की व्यवस्था करता है, सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। यदि कोई प्रयोक्ता/ग्राहक सीयूजी का निर्माण करने के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं से स्रोत प्राप्त करता है, तो सीयूजी में

शामिल सभी प्रचालक, जिनका प्रयोक्ता/ग्राहकों के साथ करार है, प्रमुख सेवा प्रदाता होंगे तथा वे सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार होंगे।

2.5 मुद्दा 4: एक अंतरसंयोजन अवयव के रूप में डीएलसी के प्रावधान पर विचार तथा इसका आरआईओ (संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव) में सम्मिलन

2.5.1 इस मुद्दे पर पण्धारकों से प्राप्त टिप्पणियों का सार बिंदु (क) से (च) में दिया गया है तथा उसके बाद आने वाले पैराग्राफों में उन पर चर्चा की गई है।

(क) स्थानीय लूप की अनबंडलिंग को अंतरसंयोजन के समान नहीं बनाया जा सकता।

(ख) प्रचालकों के बीच अंतरसंयोजन, अंतरसंयोजित प्रचालकों के सब्सक्राइबरों के बीच तथा उनके माध्यम से किसी अन्य प्रचालक के सब्सक्राइबर के साथ संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए है। इस प्रकार (सीयूजी के लिए) की अनबंडलिंग के मामले में, एक प्रचालक सर्किट के दोनों छोरों पर अपने सब्सक्राइबरों को जोड़ने के लिए दूसरे प्रचालक से क्षमता किराए पर लेता है। अतः इसे अंतरसंयोजन के रूप में बताने को कोई मामला नहीं बनता है।

(ग) स्थानीय कॉपर लीड के प्रावधान पर आरआईओ में शामिल किए जाने वाले अंतरसंयोजन अवयव के रूप में विचार करना चाहिए।

(घ) एक अंतरसंयोजन अवयव के रूप में डीएलसी का प्रावधान स्वागतयोग्य कदम है।

(ङ) डीएलसी का प्रावधान आरआईओ का भाग होना चाहिए जिसे इंकमबेंट द्वारा जारी किए जाने के लिए अधिदेशित किया जाना चाहिए।

(च) इंकम्बेटों तथा अन्य प्राइवेट प्रचालकों की बातचीत की शक्ति में असंतुलन के कारण इसे आरआईओ में सम्मिल किया जाना चाहिए।

2.5.2 प्राधिकरण ने नोट किया कि सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, आरआईओ को विशेष बाजार शक्ति (एसएमपी) द्वारा जारी किया जाता है। जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया गया है, विभिन्न सेवा प्रदाता विभिन्न एक्सेस प्रौद्योगिकियों में विशेष बाजार शक्ति होते हैं तथा स्थानीय सेगमेंट विनियम को इस अवस्था में आवश्यक नहीं माना गया है। अतः प्राधिकरण ने इन विनियमों के प्रख्यापन के पश्चात् गतिविधियों पर नजर रखने को अधिमान दिया है तथा इस अवस्था पर आरआईओ में डीएलसी/लीजड सर्किटों के प्रावधान के सम्मिलन को आवश्यकता नहीं समझा गया है।

## 2.6 मुद्दा 5: डीएलसी बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए कोई अन्य उपाय

2.6.1 इस मुद्दे पर पण्धारकों से प्राप्त टिप्पणियों का सार नीचे पैरा (क) से (ज) में दिया गया है तथा उसके बाद आने वाले पैराग्राफों में उन पर चर्चा की गई है।

- (क) पर्याप्त प्रतिस्पर्धा विद्यमान है। सेवा प्रदाताओं को अपना स्वयं की अवसरचना विकसित करनी चाहिए।
- (ख) मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) मुद्दे का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- (ग) विभिन्न डीएलसी के लिए मूल्य सीमाओं की पुनरीक्षा की जाए। छूट पारदर्शी तथा भेदभावरहित होनी चाहिए।
- (घ) एनएलडी/आईएलडी में निर्बंधनों का समाप्त करना चाहिए।
- (ङ) अवसरचना के लिए वित्तीय पहलें।
- (च) ग्राहक के परिसरों पर बहु-सेवा प्रदाताओं के अधिग्रहण की अनुमति।
- (छ) इंकम्बेट को एक समयबद्ध तरीके से डीएलसी प्रदान करना चाहिए।
- (ज) आरएफ स्पेक्ट्रम आवंटन में तेजी।

2.6.2 उठाए गए अनेक मुद्दों का या तो पहले ही समाधान किया जा चुका है या इन विनियमों के माध्यम से किया जा रहा है। मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) अभी भी एक महत्वपूर्ण कारक है तथा इसका समाधान किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा अधिक से अधिक एक्सेस/लास्टमील निर्मित की जा सके जिन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई है। तथापि, विभिन्न राज्य एजेंसियों में अंतर्गत्ता के कारण मुद्दे की जटिलता को देखते हुए, प्राधिकरण ने वर्तमान विनियमों में इस मुद्दे का निवारण करना उपयुक्त नहीं पाया है।

**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th September, 2007

**Domestic Leased Circuits Regulations, 2007**

(No. 10 of 2007)

**F. No. 404-1/2007- FN.**—In exercise of the powers conferred under Section 36, read with sub-clauses (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) of clause (b) of Sub-section (1) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997) the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations, namely :—

**CHAPTER I  
PRELIMINARY**

**1. Short title and commencement.** — (1) These regulations may be called the Domestic Leased Circuits Regulations, 2007.

(2) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.

**2. Applicability.**— These regulations shall be applicable to every service provider who can access the subscribers directly for provision of Leased Circuits under the terms and conditions of its licence.

**3. Definitions.** —In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);

(b) “Authority” means the Telecom Regulatory Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(c) “Domestic Leased Circuit” means a leased circuit to the premises of a subscriber when such premises are located within India;

(d) "Leased Circuit" means virtual private network using circuit or packet switched (Internet Protocol) technology apart from point to point non-switched physical connections or transmission bandwidth and to which the public network is not connected;

(e) "licence" means a licence granted or having effect as if granted under section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885, (13 of 1885) and Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933);

(f) 'licensee' means any person licensed under sub-section (1) of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) for providing specified public telecommunication services;

(g) "Local Lead of Domestic Leased Circuit" means the Leased Circuit between the premises of a subscriber to the nearest exchange which includes Short Distance Charging Center, point of interconnection and point of presence of the service provider from whom the subscriber obtains the Domestic Leased Circuit;

(h) "Long Distance Charging Area" means one of the several areas into which the country is divided and declared as such for the purpose of charging for trunk calls which generally is co-terminus with secondary switching area;

(i) "Prime Service Provider" means, ----

(A) in case of Domestic Leased Circuit(s) or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be, from two or more service providers in a virtual private network or Closed User Groups, the service provider who is having the agreement with the subscriber for providing such Domestic Leased Circuit(s); .

(B) in case a subscriber procures Domestic Leased Circuit from two or more service providers for the purpose of its Close User Groups, all the service providers providing Domestic Leased Circuit to such Close User Groups and having agreement with such subscriber;

(j) "regulations" means the Domestic Leased Circuits Regulations, 2007;

(k) "Short Distance Charging Center" means one of the several areas into which a Long Distance Charging Area is divided and declared as

such for the purpose of charging for trunk calls and within which the local call charges and local numbering scheme is applicable and such area coincide (except a few exceptions) with revenue tehsil or taluk in such areas;

- (l) "subscriber" includes any subscriber or any person or legal entity, which subscribes to, or avails of, any service, being the Domestic Leased Circuit from a licensee;
- (m) "service provider" means the Government as a service provider and includes a licensee;
- (n) "specified service provider" means a service provider who has been allowed under the terms and conditions of its licence to access the subscribers directly for provision of Domestic Leased Circuits;
- (o) all other words and expressions used in these regulations but not defined, and defined in the Act and the rules and other regulations made there under, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the rules or other regulations, as the case may be.

## **CHAPTER II**

### **PROCEDURE RELATING TO PROVISION OF DOMESTIC LEASED CIRCUITS OR LOCAL LEAD OF DOMESTIC LEASED CIRCUIT**

#### **4. Request for Provision of Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit.----- (1)Any specified service provider,--**

(a) who has an obligation under a contract with its subscriber or has any other arrangement with its subscriber to provide Domestic Leased Circuits; and

(b) who does not have adequate Domestic Leased Circuits or resources for to provide the same under such contract or arrangement,

may make a request in writing to any other specified service provider for providing Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be.

(2) Every service provider while making the request under sub-regulation (1) shall intimate, to other specified service provider , along with such

request the following details relating to the Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be, to be acquired from it, namely :-

- (a) specific locations, between which the Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be, is required;
- (b) the number of circuits to be acquired;
- (c) the period of lease of the Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be, to be acquired;
- (d) technical information relating to Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit to be acquired ( including its type, capacity , or bandwidth);
- (e) other relevant details.

**5. Obligation of the specified service provider, to whom request has been made under regulation 4 , to provide Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit(s).-----** (1) The specified service provider to whom request has been made under regulation 4 for provision of the Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit(s), as the case may be, shall, within thirty days of receipt of such request, send to the specified service provider who made such request(hereafter referred to as the requesting specified service provider),-----

- (a) a confirmation of its ability to provide the Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be;
- (b) a demand note giving therein the relevant details ( including charges and payment schedule), in case the other specified service provider to whom request has been made under regulation 4, confirms its ability to provide the Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be;
- (c) details of payment schedule for providing the Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be;
- (d) likely date of provisioning of the Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be, by the specified service provider .

(2) In case it is not feasible for a specified service provider, to whom request has been made under regulation 4, to provide the Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be, to the requesting specified service provider, due to reason of non-availability of capacity or technical non-feasibility, the specified service provider shall, within thirty days after the receipt of the request, intimate the same in writing indicating the reasons thereof to the requesting specified service provider.

**6. Maintenance of records in certain cases.**----- In case a specified service provider, to whom request has been made under regulation 4 to provide the Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be, is unable to provide the Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be, and intimates the reasons thereof to the requesting specified service provider, the service provider, to whom request has been made under regulation 4, shall, maintain record of each such case mentioning therein the reasons thereof and such records shall be maintained for all such cases for a period of one year beginning from the date of such intimation.

### **CHAPTER III** **RATES FOR PROVISION OF DOMESTIC** **LEASED CIRCUITS OR LOCAL** **LEAD OF DOMESTIC LEASED CIRCUIT**

**7. Tariff for Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit.**----- (1) The rates for the Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be, provided by a specified service provider to another specified service provider under these regulations [other than those cases falling under sub-regulation (2) and regulation 8] shall be such as specified under Schedule IV to the Telecommunication Tariff Order 1999, or, as may be notified by the Authority under sub-section (2) of section 11 of the Act, as the case may be.

(2) In case the rates for the Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit as referred to in sub-regulation(1) have not

been specified under the Schedule IV to the Telecommunication Tariff Order 1999, or, notified by the Authority under sub-section (2) of section 11 of the Act, the rates in such a case for the Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit provided by a specified service provider to another specified service provider under these regulations shall be such as may be mutually agreed upon between such service providers.

**8. Provision for Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit on “Rent and Guarantee Terms” or “Special Construction basis” or “Contribution basis in certain cases.”-----(1)**  
In case, the specified service provider, to whom request has been made under regulation 4,-

(a) is unable to provide the Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be, to the requesting specified service provider who made such request, due to reason of non-availability of capacity or technical non-feasibility;

(b) has intimated to the requesting specified service provider, the reasons thereof under sub-regulation (2) of regulation 5,

the specified service provider, to whom request has been made under regulation 4, shall give an option to the requesting specified service provider to acquire the Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be, on “Rent and Guarantee Terms” or “Special Construction basis” or “Contribution basis” as may be offered by it to the requesting specified service provider.

(2) The specified service provider, to whom the request has been made, under regulation 4 shall,---

(a) on receipt of confirmation from the requesting specified service provider, to whom such option had been given under sub-regulation (1), for providing the Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be, on “Rent and Guarantee Terms” or “Special Construction basis” or “Contribution basis”, as the case may be;

(b) on receipt of requisite payment from the requesting specified service provider,

provide the requesting specified service provider, the Domestic Leased

Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be, on "Rent and Guarantee Terms" or "Special Construction basis" or "Contribution basis" as may be agreed upon between them.

(3) Nothing contained in the Schedule IV to the Telecommunication Tariff Order 1999 shall apply to the Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be, provided on "Rent and Guarantee Terms" or "Special Construction basis" or "Contribution basis" as may be agreed upon between them under sub- regulation (2).

**CHAPTER IV**  
**SECURITY RELATING TO DOMESTIC**  
**LEASED CIRCUITS OR LOCAL**  
**LEAD OF DOMESTIC LEASED CIRCUIT**

**9. Security and monitoring arrangements (including lawful interception) in relation to Domestic Leased Circuits.** (1) A specified service provider, who owns the resources and provides the Domestic Leased Circuits to the subscriber, shall, without prejudice to any other law for the time being in force and the terms and conditions of its licence or any other instructions issued by the Government or any of its authorities or agencies or any liability of such subscriber,---

- (a) be responsible for bona fide use of its Domestic Leased Circuits so provided and be responsible for any misuse thereof;
- (b) be responsible for security and monitoring arrangements for Domestic Leased Circuits (including lawful interception) so provided to the subscriber.

(2) A Prime Service Provider, who ---

- (a) builds up the end-to-end Domestic Leased Circuits or virtual private network or Closed User Group,
- (b) utilises the Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, of one or more other specified service providers for the purpose of providing the Domestic Leased Circuits to the subscriber, shall, without prejudice to any other law for the time being in force and the terms and conditions of its licence or any other instructions issued by the Government or any of its authorities or agencies or liability of

such one or more other specified service providers, -

(i) be responsible for bona fide use of its Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be, so provided and be responsible for any misuse thereof;

(ii) be responsible for security and monitoring arrangements for Domestic Leased Circuits(including lawful interception).

(3) In case a subscriber avails resources from two or more specified service providers to build-up a leased circuit or virtual private network or Closed User Group, in such a case, all such two or more specified service providers having agreements with such subscriber, shall be the Prime Service Providers, and, without prejudice to any other law for the time being in force and the terms and conditions of the licence of such service providers or any other instructions issued by the Government or any of its authorities or agencies or any liability of such subscriber,-

(a) be severally and jointly responsible for bona fide use of their Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be, and be severally and jointly responsible for any misuse thereof;

(b) be severally and jointly responsible for security and monitoring arrangements for Domestic Leased Circuits(including lawful interception) provided to such subscribers.

## **CHAPTER V** **MISCELLANEOUS**

**10. These regulations not to apply in certain cases.** —Nothing contained in these regulations shall apply to any --

(a) matter or issue for which any proceedings, before any court or tribunal or under the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986) or any other law for the time being in force, are pending; or

(b) matter or issue for which a decree, award or an order has already been passed by any competent court or tribunal or authority or forum or commission, as the case may be.

(c) agreement, relating to provision of the Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be, entered

before commencement of these regulations.

**11. Application of other laws not barred.**—The provisions of these regulations shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

**12. Inspection and Auditing.**—(1) The Authority may, if it considers it expedient so to do, and to ensure compliance of the provisions of these regulations, by order in writing, direct any of its officers or employees or through one or more persons appointed by the Authority to inspect any the records maintained under regulation 6, and submit to the Authority a report in respect of such inspection.

(2) The Authority, if it considers it expedient so to do, may require any specified service provider to whom a request has been made under regulation 4, to—

(a) get the records maintained under regulation 6 audited through one or more officers or persons appointed by the Authority and submit the report in respect of such audit to the Authority;

(b) get the records maintained under regulation 6 audited through an independent agency as may be specified by the Authority and submit the report in respect of such audit to the Authority.

(3) The cost of inspection by one or more persons appointed by the Authority under sub-regulation (1) or the audit under clause (b) of sub-regulation (2) shall be borne by the concerned specified service provider

(4) The Authority may, by order or direction, from time to time, intervene, for the purpose of protecting the interest of the subscribers or specified service providers or for monitoring and ensuring provision of the Domestic Leased Circuits or Local Lead of Domestic Leased Circuit, as the case may be, under these regulations so as to promote and ensure orderly growth of the telecom sector

LAV GUPTA, Principal Advisor (FN)

[ADVT-III/IV/Exty./142/07]

**Note.—** The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Domestic Leased Circuits Regulations, 2007.

## **EXPLANATORY MEMORANDUM TO DOMESTIC LEASED CIRCUITS REGULATIONS, 2007 (10 OF 2007)**

### **1. INTRODUCTION**

**1.1** Generally Leased Circuit is a facility for communication between two or more designated points set aside for exclusive use by a customer. It could be set up as one or more point-to-point connections or as Virtual Private Network (VPN) over a shared network. Public switched network should not be connected with the leased circuit. This service may be provided over facilities owned or operated by a service provider or over transmission capacity sold or leased by another service provider. It may use terrestrial or satellite facilities, may use any media copper, fiber or wireless and may be provided through passive, circuit switched or packet switched network. Leased circuit—does not involve central office switching operations. Unlike broadband, a leased line is not contended or shared but delivers dedicated guaranteed bandwidth.

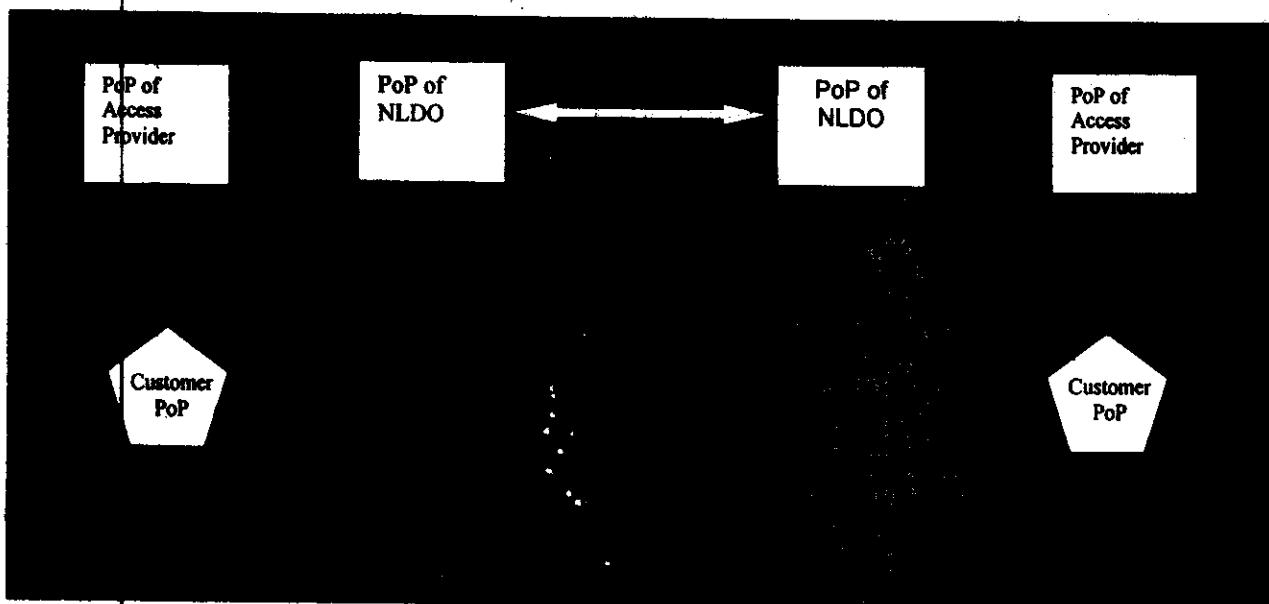
**1.2** ITU defines Leased Circuit as “a two-way link for the exclusive use of a subscriber regardless of the way it is used by the subscriber.”

**1.3** Domestic Leased Circuits (DLC) are important elements in the telecom market that telecom service providers provide to connect two or more customer sites or customers to their own or other service providers networks.

**1.4** The various elements of an end-to-end Domestic Leased Circuit (DLC) include the following segments:

- (a) Local Lead (To the nearest Point of Presence (PoP)/Point of Interconnection(POI) of Access Provider or National Long Distance Operator)
- (b) Access Segment
- (c) Trunk Segment

The schematic diagram indicating various elements of a Domestic Leased Circuit (DLC) is given below.



NLDO: National Long Distance Operator

PoP: Point of Presence

**Figure 1. Schematic diagram of a Domestic Leased Circuit(DLC)**

**1.5 Local lead** forms an essential part of the DLC. This is also referred to as terminating segment, partial circuit, tail end, local end or local leased circuit. In instances where the local lead consists of copper links, it is usually known as a local loop. It is like a leased circuit from the customer's premises to Point of Presence (PoP) or Point of Interconnection (POI) to the network operator from whom the customer obtains leased line capacity. The local lead may be

provided by a service provider other than that having contract with the customer for provision of DLC.

1.6 Local lead is part of the service provider's access network. It could take diverse forms: for a telephone customer it would primarily be copper pairs, for broadband users it could be copper pairs or fiber, for connecting enterprise EPABX it could be copper or fiber, for leased line it could be copper, fiber or wireless.

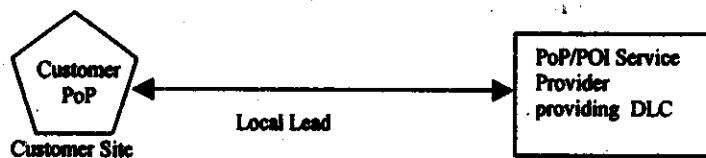


Figure2. Schematic diagram depicting local lead

1.7 **Virtual Private Network (VPN)** achieves the same purpose as physical leased circuits. VPN is configured within a public network (a carrier's network or the Internet) in order to take advantage of the economies of scale and management facilities of large networks. Therefore, in most situations, VPNs provide a user organization with the same capabilities as leased lines but at a much lower cost. Though a VPN is usually architected using the shared public infrastructure, privacy and security are maintained through security procedures and tunneling protocols. In effect, the protocols used, by encrypting data at the sending end and decrypting it at the receiving end, send the data through a "tunnel" that cannot be "entered" by data that is not properly encrypted. An additional level of security involves encrypting not only the data, but also the originating and receiving addresses.

Virtual Private Network VPNs are widely used by enterprises to create wide area networks (WANs) that span large geographic areas, to provide site-to-site connections to branch offices and to allow telecommuters to dial up their company LANs.

### **1.8 Service Providers in DLC and VPN segment**

**1.8.1** As on date, domestic bandwidth is provided to the end users by following categories of Operators in the country:

- a) National Long Distance Operators (NLDOs)**
- b) Access Service Providers (BSOs/UASPs)**

**1.8.2** As per the guidelines of Department of Telecommunications (DOT) dated 14<sup>th</sup> December 2005, the IP-II category has been abolished and no new IP-II licenses will be granted. The erstwhile IP-II players were provided option to migrate to NLD/ILD service license by paying the requisite licensing fee for each licence. Further, IP-II licensees not interested in migrating to NLD/ILD shall not be permitted to provide national/international leased line/bandwidth to individual subscribers as per existing IP-II license guidelines. As per the guidelines of DOT dated 14<sup>th</sup> December 2005, NLDOs can only access the subscribers for provision of Leased Circuits/Close User Groups (CUGs).

### **1.9 Demand for Leased Line and VPN**

**1.9.1** According to analysis of IP VPN services by IDC, the market for domestic VPN was around Rs. 216 Crores in 2003 and is expected to reach Rs 831 Crores by 2008 as shown in Table 1 below

INDIA IP-VPN SERVICES MARKET REVENUE FORECAST, IN CRORES OF RUPEES, 2003-2008						
Year	2003	2004	2005	2006	2007	2008
National IP VPN	215.6	329.5	474.9	586.8	704.1	830.9
International IP VPN	14.7	32.9	61.5	108.3	186.4	310.3

Source: IDC Report, 2003

Table 1

A similar analysis carried out by Frost & Sullivan, shows almost similar revenue projections:

IP VPN MARKET: REVENUE FORECASTS (INDIA), 2003-2009		
Year	Revenue	Revenue
	(Rs. Crores)	Growth Rate
2003	226.80	
2004	281.70	24.1
2005	387.90	37.6
2006	508.50	31.5
2007	672.30	32.0
2008	894.60	33.1
2009	1198.35	33.9

IP VPN Market: Revenue Forecast (India), 2003-2009 Source: Frost & Sullivan

Table 2

1.9.2 TRAI's Consultation Paper on "Issues Related to ISP Licence with Virtual Private Network (VPN) Dated 24th June 2005" expected point-to-point leased line market to reach Rs 1400 Crores by 2006-07

REVENUE ON ACCOUNT OF DOMESTIC LEASED CIRCUITS (IN CRORES OF RUPEES)					
FY	Actual Revenue		Projected Revenue		
	Revenue	(in Crores)	2004-05	2005-06	2006-07
	577	783.52	901.05	1081.26	1405.63

Source: TRAI's Consultation Paper on "Issues Related to ISP Licence with Virtual Private Network (VPN) Dated 24th June 2005"

Table 3

1.9.3 Revenue from point-to-point leased line reported by service providers under Basic/Unified Access License and National Long Distance License are Rs. 905 Crores and Rs. 1291 Crores

respectively for the year 2004-05 and 2005-06. It may be noted that this amount does not include the revenue generated through VPN services under Internet License. Thus the Domestic Leased circuit market is growing at very fast pace.

1.9.4 From the available data the aggregate DLC market (including VPN) is estimated to be Rs 3000 cr by 2008 and Rs 4500 cr by 2010.

**1.10 Importance of DLCs to the economy:** leased lines are and will remain a key component for the economic growth of the country. In addition these are crucial building blocks for e-business, e-governance, Internet access, BPO and IT industry. Financial, ITES, and manufacturing sector are expected to lead the IP VPN Market growth. In the financial sector banks are automating and expanding their branch networks to smaller cities. The need to connect these branches would drive the uptake for VPNs. VPNs are also being seen as a more cost effective alternative to point to point connections like VSATs. Trends by vertical segment in Indian IP VPN services over the 2003-2009 period were also given in the Frost & Sullivan Report on "Market Engineering Research for the Indian IP VPN Market."

IP VPN Market: Trends by Vertical Segment (India), 2003-2009							
Vertical Market	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
FMCG	35	25	20	20	20	15	15
Healthcare	25	20	20	20	25	20	20
Telecom/IT/High Technology	31	31	30	25	20	20	20
Banks	0	7	10	15	15	20	20
Government	5	5	5	5	5	10	10
Education	0	7	8	8	10	10	10
Others	5	5	7	7	5	5	5

IP VPN Market: forecast 2003-2009 Source: Frost & Sullivan

Table 4

1.11 Leased Lines are normally used by businesses that need high quality 24/7 interconnection, with SLA (Service Level Agreement), between geographically separated offices to run critical applications with fast upstream/downstream speeds or access to the internet. For example, remote workers accessing office-based applications will be retrieving rich multimedia data from their office databases that would require high downstream bandwidth. Knowledge Process Outsourcing (KPO)/companies and businesses providing valued added services might require high upstream bandwidth to upload large volumes of data. Internet Service Providers (ISPs) also make use of DLCs for connecting their customers to their Node for provision of leased line Internet access. Access to DLCs is therefore a critical requirement for new businesses and service providers.

1.12 Keeping in view the emerging competition arising out of certain policy initiatives of the Government like reduction in the entry barriers and license fee payable and increase in the scope of the service i.e. allowing the NLDOs to access the subscriber directly for provision of leased Circuits/Closed User Groups (CUGs), entry of number of players and increasing competitive pressure, Domestic Leased Circuit Market including the IP VPN Market is expected to grow at a healthy rate in the coming years.

1.13 The telecom services provided by the service providers to their end users largely depend on the quality and timely availability of such leased circuits. Competition in supply of all segments of end-to-end connectivity is vital to deliver retail products at a reasonable price to users. *New entrants generally find it difficult to compete in domestic leased line market because of non-availability of parts of DLC, specially the access part.* The Authority is of the view that

customer should have the ability to choose their preferred service provider of DLC without artificial and anti competitive constraint limiting their choices as they are able to do in other segments of the telecom sector

- 1.14 In today's multi operator, multi service scenario, the term access has a wide range of meanings. The Authority recognizes that in markets where some service providers rely on essential facilities provided by others for delivery of their services, it is appropriate to establish a framework to ensure that the market functions effectively.
- 1.15 In view of the above, the Authority is of the opinion that service providers shall meet other service providers' request for a complete DLC or access in terms of local lead, since denial of such request by the service provider or adduction of unreasonable terms and conditions having a similar effect, would hinder the emergence of a competitive market, or would not be in the end-user's interest. *The Authority therefore, after due diligence, decided to issue these regulations.*
- 1.16 These regulations provide a framework to ensure transparency, predictability and reasonableness and allow provision of DLC/local lead in a non-discriminatory manner. The Authority has not opted for compulsory mandation but would watch and take necessary steps as warranted by the situation in future.
- 1.17 These regulations deal specifically with domestic leased circuits and recognizing that access is essential part of building up a DLC, it becomes necessary for service providers not only to provide DLC on

request from other service providers but also the local lead in the access network in cases where the contracting service provider is able to build rest of the DLC except the local lead.

1.18 While providing DLC and/or local lead, service providers have obligation to apply equivalent conditions to other service providers providing equivalent services, and provide services under the same conditions and of the same quality as it provides to its own customers unless there are specific SLAs specifying different terms and conditions of the provision.

**1.19 Consultation Process** In order to enhance competition in Domestic Leased Circuits (DLC), the Authority initiated a consultation process in November 2006 and issued a consultation paper on "Measures to Enhance Competition in Market in India" dated 17th November 2006. Open House Discussion on the subject was also held at Delhi on 29th January 2007.

1.20 The Authority in its consultation paper Dated 17<sup>th</sup> November 2006 highlighted various issues related to promotion of competition in country's Domestic Leased Circuits (DLC) market. Following issues were raised by the Authority in the Consultation paper.

- (i) Limiting Factors for competition in DLC Market
- (ii) Whether the operator with Significant Market Power (SMP) be mandated to provide local lead for DLC and also for engineering CUGs to other operators.
- (iii) Responsibility for the Security issues.

- (iv) Whether there is a case for considering provision of DLC as an interconnection element and needs to be included in RIO(Reference Interconnect Offer)
- (v) Any other measures for promoting effective competition in DLC market.

## **2. EXAMINATION OF MAIN COMMENTS MADE AND ISSUES RAISED BY STAKEHOLDERS**

2.1 The Authority has taken various comments and inputs of the stakeholders into consideration and analysed the matter in detail. For the sake of clarity the comments made and issues raised by stakeholders are given in *italics* followed by consideration and decision of the Authority on the points.

### **2.2 ISSUE 1: Limiting Factors for competition in DLC Market**

2.2.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized below in points (a) to (m) and dealt with in the paragraphs following thereafter.

- (a) *Competition in Leased Circuit Market is not limited.*
- (b) *Competition required that competing operators should build adequate infrastructure.*
- (c) *Lack of will of private operators to develop infrastructure in all parts of their service area.*
- (d) *Private operators should be mandated to roll out their own networks to enable customers to have a choice.*
- (e) *Sharing of resources with incumbent.*
- (f) *Incumbent do not want to share their capacity for the last mile.*
- (g) *Difficulties and cost of getting ROW*
- (h) *Prices for DLC elements, timeframe of delivery*
- (i) *High cost and no fiscal incentives for laying copper*
- (j) *Microwave spectrum fee to be rationalized.*
- (k) *Absence of interconnect regulations*
- (l) *Govt policy for DLCs in rural areas*

(m) It should be mandated that one operator should provide local lead for DLC or CUG to other operator.

**2.2.2** Along with the above comments, the Authority has also taken note of other factors that were responsible for limiting competition in DLC market. The Authority also recalled various recommendations given to the Government from time to time on the subject. The Government has also taken decisions either suo-moto or based on recommendations of the Authority that have resulted in removal of some of the barriers. Some of the examples are:

Reduction of entry fee from Rs 100 crores to Rs. 2.5 Crore and reduction of license fee from 15% to 6% for NLD Licenses. IP-II service providers have also been allowed to migrate to NLD license. NLD Licensees and IP-II service providers after migration to NLD license can now access their subscribers directly for lease/data circuits for CUG and are expected to build their own last mile access network for end-to-end connectivity.

**2.2.3** The Authority is of the view that further steps need to be taken to enhance competition and to exploit full potential of DLC/VPN segment. Exploitation of this market will not only benefit the service provider and the country's economy but also provide ability to the customer to choose service provider of DLC/VPN. New entrants generally find it difficult to compete in domestic leased line market because of non-availability of parts of DLC, specially the access part and financial non-viability of expanding network in greenfield areas. ***The Authority is therefore of the opinion that there is an urgent need to issue regulations to comprehensively remove the remaining limiting factors to competition in the DLC /VPN segment.***

**2.3 ISSUE 2: Whether the operator with significant market power (SMP) be mandated to provide local lead for DLC and also for engineering CUGs to other operators.**

**2.3.1** The comments received from the stakeholders on this issue are summarized below in points (a) to (d) and dealt with in the paragraphs following thereafter.

- (a) *Concept of SMP is not relevant after 10 years of entry of private operators.*
- (b) *Incumbent is not always SMP, In case of optical/metro Ethernet and long distance bandwidth in lucrative areas Pvt. operators are SMP.*
- (c) *Incumbent should be mandated to provide DLC/ local lead to avoid duplication of resources.*
- (d) *Incumbent should provide local lead with disclosed and transparent terms and conditions.*

**2.3.2** Taking stock of the current market situation and deployment of different technologies specially in the access network the Authority feels that narrowing the obligation to only selected service providers would be a retrograde step. The concept of SMP is therefore not very relevant at this stage and any service provider who has spare capacity of copper, fiber or wireless should share it with other service providers. The available capacity of all service providers should be fully utilized for the benefit of the consumers. ***The Authority also expects that further development of the network would also continue in the long-term interest of the service providers and the consumers.***

**2.3.3** The Authority also noted that a provision already exists in the "The Telecommunication Tariff (Thirty Sixth Amendment) Order, 2005" dated 21st April 2005 to provide domestic leased circuits through utilisation of spare capacity when such capacity is available and when not available, on Rent and Guarantee Terms/ Special Construction/Contribution basis. The relevant clause is reproduced here:

*Clause 2(b) " It is mandatory for domestic leased circuits to be provided through utilization of spare capacity when such capacity is available and when not available, on Rent and Guarantee / Special Construction / Contribution basis etc. schemes, under the provisions of TTO relating to reporting requirement."*

The Authority is of the view that there is a need not only for providing DLC but also for providing local leads in case the service provider having contract or arrangement with the customer requires them.

2.3.4 The Authority has also observed that though mandate was available in the mentioned TTO, the quality of implementation would further improve if a framework or modality is prescribed through these regulations. There is also a need to make it obligatory for the service providers to intimate to the seeker within a specified time frame the availability of the DLC/local lead or otherwise. The provider should also intimate in writing to the seeker the reasons thereof. A record of all cases where the requests could not be met should be kept by the providers for future reference.

#### **2.4 Issue 3: Responsibility for security Issues in case of usage of resources from multiple service providers in a CUG Network:**

2.4.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized below in points (a) to (h) and dealt with in the paragraphs following thereafter.

- (a) *It will be highly inappropriate to make the prime service provider (in most cases BSNL) responsible for the security issues. It will be double penalty on BSNL along with the penalty of unbundling of local lead.*
- (b) *Disputes will arise among the service providers and objective of unbundling will not be met.*
- (c) *In view of security issues, difficulty in coordination in case of fault leading to service deterioration usage of resources from multiple service providers is not recommended.*
- (d) *All the service providers are to be responsible for security issues.*

- (e) *The prime service provider responsible for security issues.*
- (f) *The complete responsibility of security issues must be with in the CUG's themselves specially if customer forms his own CUG by procuring links from multiple providers*
- (g) *In case customer gets into an agreement with prime service provider for Managed Services, like VPN's, it should be the responsibility of prime service provider.*
- (h) *Segment wise responsibility of the service provider to be fixed.*

2.4.2 In this matter, the Authority noted that the licensor has already issued instructions vide its letter no. 824-42/2000-LR dated 15.07.2003 regarding utilization of resources by CUG customers through multiple licensed service operators for establishing CUG networks. The contents are, in fact, equally applicable to the provision of a leased line wherein an attempt is made to provide the long distance segment of the circuit from one operator and the local segment from another. The first paragraph, *inter alia*, indicates that a leased line with circuits taken from different operators on different segments is entirely permissible and does not require any approval or permission from the DoT, and a latter paragraph indicates that this has to be done through mutually agreed commercial agreements between the operators. Further, the last paragraph states that it shall be the responsibility of the operators to ensure that the telecom resources are used for genuine and lawful purposes.

2.4.3 The Authority noted the concern of the service providers that the incumbent is reluctant to provide 'local lead' connection as well as partial built up option to the competing service providers for the provision of leased circuits to their customers, on the plea that the incumbent has to ensure genuine and lawful use of the resources. Therefore these operators are finding it difficult to provision the resources for CUG/ Data Networks in a proper/ timely manner to their customers. In view of the above the Authority felt that there is immediate need for defining the responsibility for security issues in case of usage of resources from multiple service providers in a CUG Network.

**2.4.4 The decision of the Authority regarding the responsibility of security issues in case of usage of resources from multiple service providers in a CUG Network is:**

**In case of usage of resources from multiple service providers in a CUG Network, the prime service provider, who is having the agreement with the customer and arranges end-to-end solution to its customers by utilising resources from different service providers, should be responsible for security issues. In case, a user/customer procures sources from different service providers to engineer a CUG, then all the operators involved in the CUG having agreement with user/customers are the prime service providers and responsible for security issues.**

**2.5 Issue 4: considering provision of DLC as an interconnection element and its inclusion in RIO (Reference Interconnect Offer)**

**2.5.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized below in points (a) to (f) and dealt with in the paragraphs following thereafter.**

- (a) *The unbundling of local loop cannot be equated with interconnection.*
- (b) *Interconnection amongst the operators is to ensure communication among the subscribers of interconnected operators or through them with any other operator's subscriber. In the case of unbundling of this type (for CUG), one operator hires capacity from other operator for connecting its subscriber at both end of the circuit. Thus, there is no case for terming this as interconnection.*
- (c) *Provision of copper local lead should be considered as interconnect element to be included in RIO.*
- (d) *Provision of DLC as an interconnect element is a welcome step.*
- (e) *Provision of DLC should be part of RIO which should be mandated to be issued by incumbents.*
- (f) *Due to imbalance in the negotiating power of incumbents and other private operators, it should be included in RIO.*

2.5.2 The Authority noted that as per normal practice RIO is issued by Significant Market Power (SMP). As mentioned earlier different service providers may be significant market power in different access technologies and asymmetric regulation in the local segment is not considered necessary at this stage. **The Authority has therefore preferred to watch the developments after promulgation of these regulations and inclusion of provision of DLC/Leased Circuits in RIO is not considered necessary at this stage.**

**2.6 Issue 5: Any other measures for promoting competition in DLC market.**

2.6.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized below in points (a) to (h) and dealt with in the paragraphs following thereafter.

- (a) *There is enough competition. Service providers should develop own infrastructure*
- (b) *Right of Way (ROW) issues to be taken care of.*
- (c) *Review price ceilings for various DLCs. Discounts to be transparent and non-discriminatory.*
- (d) *Restrictions in NLD/ILD licences to be removed*
- (e) *Fiscal incentives for infrastructure*
- (f) *Permission to commission multiple service providers circuits at customer premises*
- (g) *Incumbent should provide DLC in a time bound manner*
- (h) *Speed up RF spectrum allocation*

2.6.2 A number of issues raised have either been addressed earlier or through these regulations. Right of way (ROW) is still a crucial factor and needs to be addressed so that more access/last mile is built by various service providers who have been permitted to do so. However, the complexity of the issue due to involvement of the various state agencies, the Authority does not find it appropriate to address this issue in the present regulations.